

06 अप्रैल 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

- गाजा युद्धविराम के आत्मान पर भारत एचआरसी मतदान से दूर रहा:

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

अर्थव्यवस्था:

- खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची रहने के कारण आरबीआई ने रेपो रेट को बरकरार रखा:
- आरबीआई नकदी जमा करने के लिए UPI को सक्षम बनाएगा:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

- पोल्ट्री (poultry) के विकास को बढ़ावा देने के लिए वैकी का एंटीबायोटिक दवाओं पर

जोरः

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधितः

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीयः

अंतर्राष्ट्रीय संबंधः

1. अब फ़िलिस्तीन स्वतंत्र और संप्रभु नहीं होगा:

F. प्रोलिम्स तथ्यः

1. टाइलोसिन (Tylosin):

G. महत्वपूर्ण तथ्यः

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्नः

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्नः

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधितः

गाजा युद्धविराम के आव्वान पर भारत एचआरसी मतदान से दूर रहा:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते

प्रारंभिक परीक्षा: गाजा (Gaza)।

मुख्य परीक्षा: भारत-इजरायल-फिलिस्तीन संबंध।

प्रसंग:

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council (UNHRC)) में उस प्रस्ताव से परहेज किया जिसमें गाजा में तत्काल युद्धविराम के साथ-साथ इज़राइल पर हथियार प्रतिबंध लागू करने का आव्वान किया गया था।
- इसी तरह के प्रस्तावों पर भारत के ऐतिहासिक रूख और यूएनएचआरसी में इसके मतदान पैटर्न के कारण इस निर्णय ने ध्यान आकर्षित किया।

समस्याएँ:

- गाजा युद्धविराम प्रस्ताव से परहेज: गाजा में तत्काल युद्धविराम के आव्वान वाले प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहने के भारत के फैसले ने इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष पर उसके रूख और इसे संबोधित करने में यूएनएचआरसी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

महत्व:

- पिछले वोटों के साथ तालमेल: भारत के मतदान से दूर रहने को यूएनएचआरसी के प्रस्तावों के प्रति उसके पिछले दृष्टिकोण के अनुरूप देखा जाता है जो संघर्ष की स्थितियों में जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करता है।
- चयनात्मक मतदान: युद्धविराम प्रस्ताव से दूर रहते हुए, भारत ने तीन अन्य प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, जिसमें फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना की गई और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया गया। यह

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष (Israel-Palestine conflict) के प्रति भारत के सूक्ष्म दृष्टिकोण को उजागर करता है।

समाधान:

- पारदर्शी संचार: विदेश मंत्रालय को अपने विदेश नीति निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए, गाजा युद्धविराम प्रस्ताव से भारत के दूर रहने के पीछे के तर्क पर स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए।
- संतुलित जुड़ाव: भारत को इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में कूटनीतिक रूप से शामिल रहना चाहिए, जवाबदेही और मानवाधिकारों के महत्व पर जोर देते हुए शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करनी चाहिए।

सारांश:

- गाजा युद्धविराम प्रस्ताव पर यूएनएचआरसी वोट से भारत का अनुपस्थित रहना इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के प्रति उसके सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें कूटनीतिक विचारों के साथ जवाबदेही और मानवाधिकारों की चिंताओं को संतुलित किया गया है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

खाद्य पदार्थों की कीमतें ऊंची रहने के कारण आरबीआई ने रेपो रेट को बरकरार रखा:

अर्थव्यवस्था:

विषय: भारत में आर्थिक विकास, मैक्रोइकॉनॉमिक्स।

प्रारंभिक परीक्षा: रेपो दर (Repo rate)।

मुख्य परीक्षा: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति।

प्रसंग:

- समग्र मुद्रास्फीति में कुछ कमी के बावजूद, लगातार ऊंची खाद्य कीमतों पर चिंताओं के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का विकल्प चुना है।

- यह लगातार सातवीं बार है जब आरबीआई ने ब्याज दरें बनाए रखने का विकल्प चुना है।

समस्याएँ:

- उच्च खाद्य कीमतें: खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी आरबीआई के लिए लगातार चिंता का विषय रही है, जिससे मौद्रिक नीति के संबंध में निर्णय लेने पर असर पड़ रहा है।
- मुद्रास्फीति में कमी: जबकि समग्र मुद्रास्फीति में नरमी के कुछ संकेत दिखे हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतों से संबंधित अनिश्चितताएं चुनौतियां पैदा कर रही हैं।
- विकास-मुद्रास्फीति संतुलन: उभरती विकास-मुद्रास्फीति गतिशीलता को देखते हुए आरबीआई मुद्रास्फीति (*inflation*) पर अंकुश लगाने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है।

महत्व:

- मौद्रिक नीति स्थिरता: रेपो दर (*repo rate*) को अपरिवर्तित रखने का निर्णय आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच मौद्रिक नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- मुद्रास्फीति प्रबंधन: आरबीआई के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
- आर्थिक विकास पर प्रभाव: भारत के आर्थिक सुधार पथ को बनाए रखने के लिए आर्थिक विकास के समर्थन के साथ मुद्रास्फीति नियंत्रण उपायों को संतुलित करना आवश्यक है।

समाधान:

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: आरबीआई दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति को स्थायी आधार पर अपने लक्ष्य के साथ संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।

- खाद्य मूल्य प्रबंधन: आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय खाद्य मूल्य दबाव को कम करने और मुद्रास्फीति को स्थिर करने में मदद कर सकते हैं।
- नीति संचार: आरबीआई की मौद्रिक नीति रुख और उद्देश्यों का स्पष्ट संचार बाजार की अपेक्षाओं और निवेशकों के विश्वास को निर्देशित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- डेटा निगरानी: मुद्रास्फीति के रुझानों की निगरानी करना, विशेष रूप से आवश्यक खाद्य पदार्थों में, और मुद्रास्फीति के दबावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उचित नीतिगत उपायों के साथ सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करना आवश्यक है।

सारांश:

- उच्च खाद्य कीमतों के बीच रेपो दर को बनाए रखने का आरबीआई का निर्णय मुद्रास्फीति संबंधी चुनौतियों के सामने मौद्रिक नीति के प्रति केंद्रीय बैंक के सतर्क दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। भविष्य में खाद्य मूल्य अनिश्चितताओं को दूर करने, मूल्य स्थिरता बनाए रखने और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने के ठोस प्रयास भारत की आर्थिक लचीलापन और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आरबीआई नकदी जमा करने के लिए UPI को सक्षम बनाएगा:

अर्थव्यवस्था:

विषय: संसाधन जटाना एवं विकास।

प्रारंभिक परीक्षा: नकद जमा के लिए यूपीआई।

मुख्य परीक्षा: नकद जमा के लिए यूपीआई का महत्व।

प्रसंग:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने और ग्राहक सुविधा में सुधार लाने के उद्देश्य से कई उपायों की घोषणा की है। इन पहलों में नकद जमा के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस

(Unified Payment Interface (UPI)) को सक्षम करने का प्रस्ताव रखा गया है, यह एक ऐसा कदम जो भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों की बढ़ती लोकप्रियता और स्वीकार्यता को दर्शाता है।

समस्याएँ:

- नकद जमा के लिए सीमित विकल्प: वर्तमान में, नकद जमा की सुविधा मुख्य रूप से डेबिट कार्ड के उपयोग के माध्यम से उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों की पसंद और सुविधा सीमित हो जाती है।
- ग्राहक सुविधा बढ़ाना: नकद जमा के लिए यूपीआई की शुरूआत का उद्देश्य ग्राहकों को नकदी जमा करने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करना है, जिससे यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने और इसके लाभों का लाभ उठाया जा सके।

महत्व:

- विस्तारित बैंकिंग पहुंच: नकद जमा के लिए यूपीआई को सक्षम करने से ग्राहकों के लिए उपलब्ध विकल्पों की सीमा व्यापक हो जाएगी, जिससे बैंकिंग सेवाएं अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो जाएंगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास डेबिट कार्ड नहीं हैं।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा: यह कदम वित्तीय लेनदेन की व्यापक श्रृंखला के लिए यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों के उपयोग को प्रोत्साहित करके डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर सरकार के प्रयास के अनुरूप है।
- अनिवासी निवेश को प्रोत्साहित करना: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centre (IFSC)) में पात्र विदेशी निवेशकों को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) में निवेश करने की अनुमति देना टिकाऊ निवेश उपकरणों में अधिक भागीदारी को बढ़ावा देता है, जो पर्यावरणीय लक्ष्यों में योगदान देता है।

समाधान:

- परिचालन दिशानिर्देश: आरबीआई मौजूदा बैंकिंग प्रणालियों में निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए नकद जमा सुविधाओं के लिए यूपीआई के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए परिचालन निर्देश जारी करेगा।
- नियामक ढांचा: टिकाऊ निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, सरकार और संबंधित अधिकारियों के परामर्श से, आईएफएससी में एसजीआरबी में विदेशी निवेश के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करना।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: निवेशकों की पहुंच बढ़ाने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप विकसित करना।

सारांश:

- नकद जमा के लिए यूपीआई को सक्षम करने, ग्रीन बांड में विदेशी निवेश की अनुमति देने और रिटेल डायरेक्ट योजना के लिए एक मोबाइल ऐप पेश करने की आरबीआई की पहल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। ये उपाय न केवल ग्राहकों को बैंकिंग लेनदेन में अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं बल्कि भारत में स्थायी निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान की उत्तरति में भी योगदान देते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

पोल्ट्री (poultry) के विकास को बढ़ावा देने के लिए वेंकी का एंटीबायोटिक दवाओं पर जोर:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास, रोजमर्रा की जिंदगी में वैज्ञानिक विकास के अनुप्रयोग।

प्रारंभिक परीक्षा: एंटीबायोटिक्स (Antibiotics)

मुख्य परीक्षा: विकास प्रवर्तक के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग का मुद्दा।

प्रसंग:

- ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म (टीबीआईजे) के अनुसार, पोल्ट्री निर्माता वेंकीज़ अपने विपणन और किसानों को एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री के लिए जांच के दायरे में आ गए हैं, जो दवा प्रतिरोधी संक्रमण के प्रसार में योगदान दे रही है।
- यह विश्लेषण पोल्ट्री उद्योग में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को संबोधित करने के लिए वेंकी की प्रथाओं, उनके महत्व और संभावित समाधानों से जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालता है।

समस्याएँ:

- एंटीबायोटिक का दुरुपयोग: वेंकीज़ डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के विपरीत, विकास को बढ़ावा देने और निवारक उपयोग सहित गैर-चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किसानों को एंटीबायोटिक दवाओं का विपणन कर रहा है।
- यह अभ्यास जानवरों और मनुष्यों दोनों में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास में योगदान कर सकता है।
- गंभीर औषधि उपयोग: वेंकी के उत्पादों में डब्ल्यूएचओ (WHO) द्वारा वर्गीकृत एंटीबायोटिक्स शामिल हैं जो मानव चिकित्सा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि टाइलोसिन, एमोक्सिसिलिन और नियोमाइसिन, जो मानव स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं।
- विनियमन का अभाव: उचित पशु चिकित्सा नुस्खे और निरीक्षण के बिना इन एंटीबायोटिक दवाओं की उपलब्धता पोल्ट्री उद्योग में एंटीबायोटिक उपयोग की निगरानी और नियंत्रण में नियामक अंतर को इंगित करती है।

महत्व:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम: एंटीबायोटिक प्रतिरोध सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है, जिससे संक्रमण के इलाज में महत्वपूर्ण दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और रुणता और मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है।

- वैश्विक प्रभाव: मुर्गी पालन में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के वैश्विक प्रसार में योगदान देता है, जिससे दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
- कॉर्पोरेट जिम्मेदारी: पोल्ट्री उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, वेंकीज़ को इन नैतिक प्रथाओं का पालन करने और लाभ के उद्देश्यों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को प्राथमिकता देने की जिम्मेदारी है।

समाधान:

- विनियामक प्रवर्तन: बिक्री और नुस्खे पर कड़े नियंत्रण सहित पशुधन खेती में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंधों की निगरानी और लागू करने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करना।
- शिक्षा और जागरूकता: किसानों, पशु चिकित्सकों और उपभोक्ताओं को एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के जोखिमों के बारे में शिक्षित करना, वैकल्पिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और जिम्मेदार एंटीबायोटिक प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।
- उद्योग जवाबदेही: पोल्ट्री उत्पादकों को उनके एंटीबायोटिक विपणन और बिक्री प्रथाओं के लिए जवाबदेह बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और टिकाऊ और नैतिक उत्पादन विधियों को प्रोत्साहित करना।
- अनुसंधान और नवाचार: पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी की रोकथाम और विकास को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों जैसे प्रोबायोटिक्स, टीके और बेहतर स्वच्छता प्रथाओं के अनुसंधान और विकास में निवेश करना।

सारांश:

- पोल्ट्री फार्मिंग में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग, जैसा कि वेंकी की प्रथाओं से उदाहरण मिलता है, एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है और नियामक हस्तक्षेप और उद्योग जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। एंटीबायोटिक

प्रतिरोध को संबोधित करने के लिए भावी पीढ़ियों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता को सुरक्षित रखने एवं खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, उद्योग के खिलाड़ियों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

संपादकीय-द हिन्दू

संपादकीय:

अब फ़िलिस्तीन स्वतंत्र और संप्रभु नहीं होगा:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत के हितों पर भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव।

मुख्य परीक्षा: फ़िलिस्तीन का मुद्दा।

प्रसंग:

- समकालीन मध्य पूर्व में, एक स्वतंत्र, संप्रभु फ़िलिस्तीनी राज्य की इज़राइल के साथ शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व की संभावना तेजी से दूर होती जा रही है। पिछली बातचीत और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, हाल के घटनाक्रम ने दो-राज्य समाधान की व्यवहार्यता पर संदेह पैदा कर दिया है।

पृष्ठभूमि:

- 7 अक्टूबर, 2023 से पहले, कुछ चेतावनियों के साथ भी, किसी समय में फ़िलिस्तीनी राज्य के उभरने की कुछ संभावना थी।
- दो-राज्य समाधान कैसा होगा, इसका विस्तृत रोडमैप तैयार करने के लिए दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई।

- जनवरी 2001 में, ताबा (Taba) में, वे एक समझौते पर पहुँचने के करीब पहुँच गये थे।

हमास बनाम फिलिस्तीनी प्राधिकरण:

- हमास के बढ़ते प्रभाव और इजरायलियों के बीच फिलिस्तीनी राज्य के लिए घटते समर्थन को देखते हुए, 7 अक्टूबर के बाद दो-राज्य फॉर्मूला के पुनरुत्थान को संदेह के साथ देखा जा रहा है।
- वेस्ट बैंक में हमास की बढ़ती लोकप्रियता फिलिस्तीनी प्राधिकरण के इजरायल के साथ मध्यम रुख और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- प्रष्ठाचार और अक्षमता के आरोपों से फिलिस्तीनी प्राधिकरण की विश्वसनीयता कम हो गई है, जिससे हमास भविष्य के चुनावों में एक मजबूत दावेदार बन गया है।
- हमास का उन्मूलन अप्राप्य (कठिन) प्रतीत होता है, जिससे संघर्ष लंबा हो जाएगा और राफा पर आक्रमण जैसी सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

समस्याएँ:

- राजनीतिक ध्रुवीकरण: हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच मतभेद शांतिपूर्ण समाधान पर आम सहमति प्राप्त करने के प्रयासों को जटिल बनाता है।
- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की मौजूदगी तनाव बढ़ाती है और इजरायली सरकार से निर्णायक कार्रवाई की मांग को बढ़ाती है।
- क्षेत्रीय अस्थिरता: गाजा संघर्ष के व्यापक क्षेत्रीय टकराव में बदलने का जोखिम है, जिसमें लेबनान, सीरिया, ईरान और संभावित रूप से मिस्र में हिजबुल्लाह शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप: संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अमेरिका की भागीदारी सहित राजनयिक प्रयासों के बावजूद, स्थिति अस्थिर बनी हुई है, जिससे बाहरी शक्तियों के संघर्ष में शामिल होने का खतरा है।

महत्व:

- इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को संबोधित करने में विफलता न केवल मानवीय पीड़ा को बढ़ाती है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।
- बढ़ते तनाव के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, मौजूदा भू-राजनीतिक दोष रेखाएँ और अधिक गंभीर हो सकती हैं और मध्य पूर्व में शांति और सहयोग के प्रयास कमज़ोर हो सकते हैं।

समाधान:

- राजनयिक जुड़ाव: अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को इज़राइल और फिलिस्तीनी गुटों के बीच बातचीत और संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयासों को दोगुना करना चाहिए।
- संघर्ष शमन: जीवन की और अधिक हानि एवं बुनियादी ढांचे की क्षति को रोकने के लिए अस्थायी युद्धविराम जैसे तत्काल उपाय आवश्यक हैं।
- मूल कारणों को संबोधित करना: दीर्घकालिक समाधानों के लिए सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक मताधिकार सहित अंतर्निहित शिकायतों को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- बहुपक्षीय सहयोग: क्षेत्रीय शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को तनाव कम करने और स्थायी शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना चाहिए।

सारांश:

- इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए दूरगामी प्रभाव वाला एक अस्थिर प्लैशप्वाइंट बना हुआ है। हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच जटिल गतिशीलता को संबोधित करना, व्यापक संघर्ष बढ़ने के जोखिम को कम करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना दशकों पुराने विवाद का न्यायसंगत और स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए जरूरी है। निष्क्रियता के संभावित परिणामों को नजरअंदाज करने से इसमें शामिल सभी हितधारकों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

प्रोलिम्स तथ्य:

1. टाइलोसिन (Tylosin):

- टाइलोसिन - पशु चिकित्सा देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक रोगाणुरोधी (antimicrobial)।
- समस्या यह है कि इसके कुछ प्रकार का उपयोग मनुष्यों में भी किया जाता है, इसलिए बड़ी मात्रा में सेवन करने पर एएमआर (AMR) बनाने की संभावना हो जाती है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत में रेपो रेट के बारे में निप्रलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- I. यह वह दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है।
- II. रेपो रेट में कमी से व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण सस्ता हो जाता है।
- III. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) रेपो रेट निर्धारित करती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निप्रलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: c

प्रश्न 2. भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के संबंध में निप्रलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

कथन-I: खाद्य मुद्रास्फीति खाद्य कीमतों में बदलाव को दर्शाती है और हेडलाइन का एक घटक है।

कथन-II: कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर वस्तुओं को मुद्रास्फीति की गणना से बाहर

रखा गया है।

कथन-III: आपूर्ति में व्यवधान और मौसमी बदलाव जैसे कारक खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) केवल I और II
- (b) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II, और III

उत्तर: d

प्रश्न 3. भारतीय संसद की कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- I. प्रश्नकाल - संसद सदस्य सरकारी नीतियों और कार्यों के बारे में मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं।
- II. शून्यकाल - सांसद इस एक घंटे के दौरान पूर्व सूचना के साथ महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं।
- III. स्थगन प्रस्ताव - जिन अत्यावश्यक मामलों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उन पर चर्चा के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता था।

विकल्प:

- (a) केवल I और II
- (c) केवल II और III
- (c) केवल I और III
- (d) I, II, और III

उत्तर: c

प्रश्न 4. राखीगढ़ी हड्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

कथन 1: यह भारत में उत्खनन से प्राप्त सबसे बड़ी हड्पा बस्तियों में से एक है।

कथन 2: पुरातात्त्विक साक्ष्य राखीगढ़ी में एक अच्छी तरह से विकसित जल निकासी प्रणाली की उपस्थिति का सुझाव देते हैं।

कथन 3: सिंधु लिपि को पूरी तरह से राखीगढ़ी में पाए गए निष्कर्षों के आधार पर समझा गया है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: b

प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: मार्सुपियल्स भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं।

कथन-II: मार्सुपियल्स केवल पर्वतीय घास के मैदानों में ही पनप सकते हैं, जहां कोई शिकारी नहीं होता।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या है
- (b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I के लिए सही व्याख्या नहीं है
- (c) कथन-1 सही है कथन-2 गलत है
- (d) कथन-1 गलत है लेकिन कथन-2 सही है

उत्तर: c

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने में भारत की विदेश नीति रणनीति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। उदाहरण सहित समझाते हुए प्रमुख वैश्विक हितधारकों के साथ अपने राजनयिक जुड़ाव और संबंधों पर भारत के निर्णयों के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन - II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध) (Evaluate the effectiveness of India's foreign policy strategy in promoting its global standing and addressing pressing international issues. Provide examples and analyse the implications of India's decisions on its diplomatic engagements and relationships with key global stakeholders. (10 Marks 150 words) (General Studies – II, International Relations))

प्रश्न 2. रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ने में योगदान देने वाले कारकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। (10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन - III, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) (Discuss the factors contributing to the rise of antimicrobial resistance and its implications for public health, agriculture, and the environment. (10 Marks 150 words) (General Studies – III, Science and Technology))

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU'S की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)